'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2013-15
WPP Licence No.- U(C)-101/2013-15
R.N.I. No. 68180/98

प्रकाशन तिथि- 31 मई, 2014

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल ग्रोव रोड, क्लॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 23354841-42

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

● वर्ष : 17 ● अंक 13 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● 16 से 31 मई, 2014

डॉ. उदित राज को भारी मतों से जिताने व सहयोग के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद

परिसंघ का विस्तार करें

डॉ. उदित राज

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ का गठन मूलतः पांच आरक्षण विरोधी आदेशों के विरूद्ध हुआ था। ज्ञात रहे कि सन् 1997 में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने पांच आरक्षण विरोधी आदेश जारी किए थे और उन्हीं की वापसी के लिए परिसंघ का निर्माण हुआ। वे उद्देश्य तो लगभग पूरे हो गए और उसके बाद समय-समय पर तमाम चुनौतियां मिलती रही, जिसका मुकाबला संघर्षो के माध्यम से किया जाता रहा है। 17 साल तक शायद ही सामाजिक आंदोलन की जिंदगी होती है अगर हुआ तो वह अपवाद ही है। अब समय आ गया है कि इसको विस्तारित करें। नेतृत्व अभी तक कर्मचारियों एवं अधिकारियों के हाथ में रहा है। इससे जुड़े लाखों कर्मचारी सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। यह भी सोचा गया था कि इसको गांव और गली तक पहुंचाया जाए, अभी तक वह संभव नहीं हुआ।

राजनैतिक दल दलितों की बात करना लगभग बंद कर दिए हैं। इसका कारण है कि उन्हें लगता है कि दलितों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। यह पार्टी स्वयं दलित-आदिवासी मुद्दों को नहीं उठाती है। ऐसे में एक शक्तिशाली सामाजिक आंदोलन की आवश्यकता है। इन्हीं परिस्थितियों में परिसंघ का विस्तारीकरण अब गांव तक होना चाहिए। यदि सामाजिक आंदोलन मजबूत होगा तो हमारी मांगें भी स्वीकार किए जाएंगे। 10 सालों के दौरान कांग्रेस की सरकार ने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिसका उल्लेख किया जाए। दूसरी सच्चाई यह है कि सामाजिक आंदोलन का दबाव भी कम रहा। तमाम सामाजिक गतिविधियां तो होती रही लेकिन उनकी दिशा ठीक नहीं थी। वे आलोचनात्मक एवं सैद्धांतिक पक्ष तक सीमित रहे। ब्राह्मणवाद की आलोचना करने से समाज को भागीदारी नहीं मिलेगी बल्कि अधिकारों को लेकर के संघर्ष करना पड़ेगा। मैं संसद में पहुंच गया हूं उससे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ना निश्चित है और इससे संगठन गांव-गांव तक फैलाया जा सकता है। यदि हमारा सामाजिक आंदोलन मजबूत रहेगा तो पार्टी भी हमारी बातों को मानेगी। देश के हर जिले, तहसील और गांव तक संगठन खड़ा करने के लिए संकल्प लेना पड़ेगा।

डॉ. उदित राज ने भारी मतों से जीत दर्ज की

विनोद कुमार

उत्तर पश्चिमी दिल्ली संसदीय सीट से डॉ. उदित राज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ ने दलित भागीदारी, क्षेत्र का विकास एवं देश की एकता एवं अखंडता के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव में हिस्सा लिया। जिनका नाम भारतीय दलित राजनीति में बड़े सम्मान से लिया जाता है। जिस दिन से उदित राज ने सोलहवीं लोकसभा चुनाव के लिए अपना पर्चा दाखिल किए उसी समय से समस्त दलित समाज एवं क्षेत्रीय निवासियों के बीच में हर्षोउल्लास का माहौल छा गया और उसी दिन उत्तर-पश्चिमी लोकसभा के निवासियों ने निश्चय कर लिया कि क्षेत्र के विकास एवं सामाजिक सौहार्द के लिए राष्ट्रीय दलित नेता डॉ. उदित राज को ही भारी मतों से जिताकर संसद में भेजेंगे।

चुनाव का संचालन सी-9/90, सेक्टर-8, रोहिणी, नई दिल्ली से जयभगवान अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया और लोकसभा के अंतर्गत आने वाली सभी 10 विधानसभाओं में चुनावी कार्यालय खोले गए और क्षेत्रीय स्तर पर भाजपा के जिला एवं मंडल पदाधिकारियों ने चुनाव में मजबूती से प्रचार-प्रसार कर लोगों को डॉ. उदित राज के पक्ष में वोट देने की अपील की।

पर्चा दाखिल करने के दिन से ही परिसंघ के समस्त प्रदेशों के समस्त पदाधिकारियों, सफाई कामगार संगठनों का परिसंघ के समस्त नेताओं एवं कार्यकर्ताओं एवं देश के कोने-कोने से आए शुभचिंतकों ने दिल्ली आकर उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र में डॉ. उदित राज के लिए उनके पूर्व में समाज हित में किए गए कार्यो के आधार पर जनता को उनके कार्यो के बारे में अवगत कराया और डॉ. उदित राज के पक्ष में मतदान करने की अपील की।

चुनाव में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी की राखी बिड़ला एवं कांग्रेस की कृष्णा तीरथ के बीच रहा। डॉ. उदित राज ने निकटतम प्रतिद्वंदी राखी बिड़ला को 1.06 लाख मतों से पराजित कर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर उत्तर-पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने।

भाजपा के उदितराज 629860 वोट लेकर विजयी रहे। वहीं राखी को 523058 वोट मिले। जीत-हार का अंतर 106802 मतों का रहा। कांग्रेस की उम्मीदवार व मौजूदा सांसद कृष्णा तीरथ को कुल 157242 वोट ही मिले।

16 मई को मतगणना केंद्र पर सुबह से उम्मीदवारों व उनके सर्मथकों का आना शुरू हो गया था। रुझान आने के साथ-साथ नेताओं के चेहरों के हावभाव बदलते रहे। एक समय ऐसा भी आया जब 'आप' की उम्मीदवार राखी बिड़ला मतगणना केंद्र छोड़ कर चली गईं। मतों का अंतर कुछ कम होने की जानकारी मिलने पर वे दोबारा अपने समर्थकों

शेष पृष्ठ 2 पर...

भारी मतों से चुनाव जीतने के तुरंत बाद अपार समर्थकों के साथ सांसद डॉ. उदित राज

चुनाव जीतने के बाद आनंदित मुद्रा में डॉ. उदित राज अपनी पत्नी सीमा राज के साथ(बीच में) एवं अन्य

सामाजिक क्रांति के लिए टोपी नहीं खोपड़ी बदलनी होगी

एस. एल. सागर

हम दुनिया का सामाजिक सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक परिवर्तन का इतिहास पढ़ते हैं किंतु इस परिवर्तन की दिशा में क्रांतियों और क्रांतिकारियों के इतिहास का भारत स्वयं एक ऐतिहासिक स्थल रहा है। टर्की में जो कमाल पासा ने किया, उसे धार्मिक क्रांति कह सकते हैं। रूस-चीन में आर्थिक क्रांति कार्ल मार्क्स के विचारों से आई। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इन क्रांतियों से देशों की सभ्यता, संस्कृति, धार्मिक विचाराधारा तथा आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था बदली। इन सारे परिवर्तन के पीछे सोच का परिवर्तन ही कारण था इसलिए विद्वानों का यह कथन सही मालूम पड़ता है कि यदि सामाजिक बदलाव लाना है तो उसके लिए टोपी नहीं खोपड़ी बदलनी होगी।

जब सोच बदलता है अर्थात् मस्तिष्क (खोपड़ी) में बदलाव आता है तो विचार एवं सोच में बदलाव के साथ समाज, धर्म, संस्कृति सब बदल जाते हैं। उसके बाद नए समाज का निर्माण होता है। भारत के हर शहर-कस्बे में पांच आदमियों में तीन यह कहते हुए सुने जाते हैं कि अब जातिवाद, वर्ण भेद जैसा सामाजिक विभाजन और उसके फलस्वरूप पैदा होने वाला भेदभाव कहां रह गया है। ऐसा कहना उतना ही बड़ा झूठ है जितना यह बताना कि सूरज का पश्चिम से उदय होना। आज जीवन का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां हर सोच जातिवाद के आधार पर तय न होता हो। यहां जन्म, जीवन एवं मृत्यु तक में जाति है क्योंकि यहां मरघट भी जाति के आधार पर मिलता है। जन्म लेते ही हर आदमी का जाति आधारित संस्कार होता है। द्विजों का जाति संस्कार वेदमंत्रों के साथ और शूद्रों का मंत्र रहित होता है। बड़े होने पर विवाह संस्कार जाति के अनुसार निर्धारित मंत्रों के साथ होता है जबकि शूद्रों की किसी भी जाति में विवाह संस्कार मंत्र रहित होता है और जब आदमी मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार भी जाति के नियमों के अनुसार ही होता है। जाति के आधार पर धार्मिक संस्कार अलग-अलग होते हैं। मंदिर का महंत या पुजारी केवल ब्राह्मण ही हो सकता है, शूद्र महंत नहीं बन सकता। यहां तो देवता भी वर्णों के अनुसार बंटे हुए हैं। ब्रह्म ब्राह्मणों, विष्णु क्षत्रियों और महादेव शूद्रों के देवता हैं। वहीं कुबेर वैश्यों, चित्रगुप्त कायस्थों तथा विश्वकर्मा बढ़ई और लोहारों के पूज्य हैं। हम कह सकते हैं कि भारत में तो देवताओं की भी जाति होती है। इस देश में तो जानवर भी जातियों में बंटे हुए हैं। यहां गाय ब्राह्मण, शेर क्षत्रिय, घोड़े वैश्य तथा गधा शुद्र का होता है। जानवरों की भांति यहां पक्षी भी जातियों में बंटे हुए हैं। हंस ब्राह्मण तो कबूतर वैश्य का होता है। ब्राह्मणों ने दिशाओं का नामकरण भी कर रखा है। पूर्व दिशा ब्राह्मण, पश्चिम क्षत्रिय, उत्तर वैश्य तथा दक्षिण शूद्र के लिए होता है। ब्राह्मणों ने भारत के दानों में भी वर्ण व्यवस्था कायम कर रखी है। गेहूं ब्राह्मण, चना क्षत्रिय, जौ वैश्य तो मटर शूद्र का प्रतीक है। ब्राह्मणी विधान ने आदमी के शारीरिक चिह्न भी वर्णानुसार बांट रखे हैं। चोटी ब्राह्मण, मूंछ क्षत्रिय, पगड़ी वैश्य और जूती शूद्र के लिए होता है। यहां ब्राह्मण देवता ने आदमी के शरीर के टुकड़े कर उसको भी वर्णानुसार चार हिस्सों में बांट रखा है। सिर ब्राह्मण, सीना-भूजा क्षत्रिय, उदर वैश्य और पैर शूद्र के लिए बना रखे हैं। हमें देखने को मिलता है कि यहां आदमियों का नामकरण भी वर्णानुसार रखे जाते हैं। ब्राह्मण बालक का नाम कल्याण प्रसाद, क्षत्रिय का कल्याण सिंह, वैश्य का कलियान तथा शूद्र बालक का नाम कल्लना रखा जाता है।

भारत में धर्म, रक्षा, व्यापार सहित कृषि और सेवा कर्म भी वर्ण जातियों के आधार पर बांटे जाते रहे हैं। हमारे देश में छोटे-बड़े 20 लाख मंदिर है। हर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण ही होता है, यह पूछने की जरूरत नहीं है। विजयदशमी के दिन क्षत्रिय शस्त्रों का प्रदर्शन कर जाति का जुलूस निकालते हैं। जाति के आधार पर व्यापार मंडल केवल वैश्यों की ही संस्था है। आज भी देशभर में मरे जानवरों का चमड़ा उतारने का काम चमार ही करता है और कपड़े धोने का काम जाति के आधार पर धोबी ही करता है। देखने से स्पष्ट है कि पूरे देश में जातिवाद छाया हुआ है।

जाति के आधार पर केवल भंगी ही सारे देश में मैला उठाने का काम काम करता है। लाख गुना पगार देने पर भी यह काम कोई ब्राह्मण नहीं करेगा। बिहार का द्विज आज भी हल का मुठिया नहीं पकड़ता क्योंकि यह उसके जाति/धर्म के विरुद्ध होगा। नदियों के नाव चलाने का काम सर्वत्र मल्लाह जाति के लोग ही करते हैं। कहीं कोई ब्राह्मण नाव चलाते हुए नहीं मिलेगा। आज भारत भूमि का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां जातिवाद का नंगा नाच न हो रहा हो। जाति का प्रभाव भोजन, पानी और पेशे तक ही सीमित नहीं है बल्कि गांव में किस जाति के लोगों के घर किस दिशा में होंगे, यहां का जातिवाद यह भी तय करता है।

हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने जातिवादी की विभीषिका को देखकर उसके दुष्परिणामों को समझते हुए आरक्षण की व्यवस्था की थी, उसका आधार भी जाति ही माना है। आज हर काम जाति के आधार पर ही होता है। जाति के आधार पर सरकार जाति प्रमाणपत्र बांटती है। धर्म और जातियों के आधार पर राजनैतिक दल बने हुए हैं। हर जाति जातीय संगठन बनाकर उसका नामकरण भी जाति के आधार पर कर रहे हैं जैसे- यादव महासभा, ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय महासभा, वैश्य एकता परिषद, बाल्मीकि विकास परिषद, आदि-आदि।

ऊंच-नीच के आधार पर जातियों के बीच आपस में कटु द्वेष रहता है। ऊंची जातियां नीची जातियों को अपने समकक्ष नहीं आने देती है। यदि कोई नीची जाति ऊंची जाति की बराबरी करे तो ऊंची जाति वाले नीची जातिवाले को मारते-पीटते हैं। जाति द्वेष के कारण ऊंची जाति के लोग नीची जाति वालों की बारातें घोड़े पर नहीं निकलते देते हैं। भारत में जातिवाद का जहर इस सीमा तक भरा हुआ है कि एक ऊंची जाति की कुतिया किसी नीची जाति के व्यक्ति के दरवाजे पर पहुंच जाए और वह नीची जाति का व्यक्ति कुतिया को भूखा समझकर रोटी खिला दे तो वह कुतिया भी अछूत मानी जाती है और बेचारे उस अछूत जाति के व्यक्ति को दंड भोगना पड़ता है। आज सरकार का पंजीकरण विभाग जातियों के नाम से जातीय संस्थाओं का पंजीकरण कर रहा है। पूरे देश में नगरों की गलियों-मोहल्लों के नाम जाति के नाम पर रखे जाते हैं जैसे – अग्रवाल मोहल्ला, यदुवंश नगर मोहल्ला, मतिहाराना, चौधिराना, पुरोहिताना, कुम्हार मंडी, खटीक गली आदि-आदि।

आज जाति के नाम पर राजनीति करना असंवैधानिक नहीं माना जा रहा है। हमारे देश में जाति व्यवस्था पूरी तौर से हावी है और उसे हर स्तर पर स्वीकृति प्रदान की जाती है। भारत में जाति एक तथ्य है जो इसे झुठलाने की बात करता और कहता है कि जाति भेदभाव कहां रहा है तो वह या तो झूठा-मक्कार या घोर स्वार्थी है जो केवल दलितों को मिले जाति आधारित सुविधाएं-आरक्षण आदि उनके अधिकारों को मारने की बात करता है।

किंतु हमारे देश में जाति व्यवस्था की एक अनोखी विशेषता है। हर जाति की जरूरत अपनी है। उनकी सभी सीमाएं अपनी हैं और उनका भविष्य अपना है किंतु कार्य निर्धारित करना दूसरे के हाथ में है। इसी कारण से कुछ जातियों की गुलामी भोगनी पड़ती है। जिन लोगों को दलित-पिछड़ों की अस्मिता निर्धारण का अधिकार है उन्हें धर्म के कानून ने यह अधिकार देकर उनका संरक्षण सुनिश्चित कर रखा है।

दलित-पिछड़ों की कमजोरी यह है कि ये जातियां अपना निर्णय भावनागत करती आ रही है। इन्होंने कभी अपना रास्ता तर्क के प्रयोग पर तय नहीं किया। भावनाशील होने के कारण ही ये सारे अद्विज-द्विजों के गुलाम बने और मनुवाद का बोझ ढोते रहे और हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी एक कुटिल तबके की गुलामी करते रहे। इन दलित-पिछड़ों ने अपने निर्णय सदैव दिल से लिए दिमाग से नहीं किए, यही इनकी त्रासदी का मूल कारण है।

शेष अगले अंक में...

अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रों के लिए
निःशुल्क उच्च शिक्षा का बेहतरीन मौका

आर्थिक कठिनाइयों के कारण दलित छात्र उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जो चिंता का विषय है। अजा/जजा परिसंघ के रा0 चेयरमैन, डॉ0 उदित राज जी, सभी शिक्षण संस्थानों से अपील करते रहे हैं कि वे अपने यहां दलित छात्रों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करके अपने सामाजिक दायित्वों को निभाएं। इसी क्रम में भगवान महावीर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के चेयरमैन डॉ0 संजय जैन ने वायदा किया है कि वे अपने संस्थान में यथासंभव दलित छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देंगें। इनके संस्थान में निम्नलिखित उच्च तैकनिक पाठ्यक्रमों की सुविधा है -

B.Arch, Polytechnic Diploma, B.Tech, M.Tech, BBA, BCA, D.Ed.,
JBT, B.Ed., M.Ed., B.Pharma, M. Pharma, C.Ped, B.P.Ed., M.P. Ed.

contact
(A Group of Jain Minority Institutions)
Bhagwan Mahaveer Group of Institutions
(Approved by AICTE, New Delhi, Ministry of HRD, Govt. of India,
& Affiliated to DTE, Haryana and DCR University of Science & Technology
Murthal, Sonepat (Haryana))
For Admission & Other details Visit at www.msitsnp.in or Contact :-
Prof : (Dr.) Sanjay Jain, Chairman, M.- +91-9810628607
Prof : (Dr.) O. P. Sharma, Registrar, M.- +91-8607400783 &
Hostel facility available on payment basis.

शेष पृष्ठ 1 का...

डॉ. उदित राज ने भारी मतों से जीत दर्ज की

के साथ आई।

21 चरणों में हुई मतगणना की शुरुआत से ही डॉ. उदित राज बढ़त बनाए रहे। 'आप' उम्मीदवार भी लगातार उसके पीछे बनी रहीं। वहीं कांग्रेस की उम्मीदवार कुछ चरणों के बाद ही पिछड़ गई। मतगणना के सातवें चरण के नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार कृष्णा तीरथ मतगणना केंद्र छोड़ कर चली गईं। आंठवें व नौवें चरण में भाजपा व 'आप' के बीच मतों का अंतर करीब नब्बे हजार था और अंततः डॉ. उदित राज ने राखी बिड़ला को भारी मतों से हराने में सफलता प्राप्त की।

यह ज्ञात हो कि डॉ. उदित राज दलित राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखते हैं। इस ऐतिहासिक जीत पर डॉ. उदित राज ने कहा कि मेरी जीत का श्रेय मोदी जी, भाजपा के समस्त नेता एवं कार्यकर्ता, क्षेत्रीय जनता सहित समस्त दलित समाज को जाता है। इसके लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई।

इस ऐतिहासिक जीत पर समस्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, क्षेत्रीय निवासियों, परिसंघ के समस्त क्रांतिकारी नेताओं-कार्यकर्ताओं एवं सफाई कामगार संगठनों का परिसंघ के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को बहुत-बहुत बधाई।

दलित-जातिवादी राजनीति बनाम हिंदुत्व

तुलसीराम

पिछले 25 सालों में दलितों के साथ पिछड़े वर्ग की राजनीति में जातिवाद अपनी चरम सीमा पार कर गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि विशुद्ध हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भाजपा ने अकेले बहुमत पाकर भारत की सत्ता प्राप्त कर ली। भारतीय जाति-व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि इसे धर्म और ईश्वर से जोड़ दिया गया। यही कारण था कि इसे ईश्वरीय देन मान लिया गया। गांधीजी जैसे व्यक्ति भी इसी अवधारणा में विश्वास करते थे। इस अवधारणा का प्रचार सारे हिंदू ग्रंथ करते हैं। इसलिए हिंदुत्व पूर्णरूपेण जाति-व्यवस्था पर आधारित दर्शन है।

विभिन्न जातियां हिंदुत्व की सबसे मजबूत स्तंभ हैं। इसलिए इन स्तंभों की रक्षा के लिए ही भारत के सभी देवी-देवताओं को हथियारबंद दिखाया गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि दलितों पर आज भी वैदिक हथियारों से हमले जारी हैं। ऐसी स्थिति में जब जाति को मजबूत किया जाता है, तो हिंदुत्व स्वतः मजबूत होता चला जाता है। पिछले 25 वर्षों में ऐसा ही हुआ है।

नब्बे के दशक में कांशीराम ने एक अत्यंत खतरनाक नारा दिया था- 'अपनी-अपनी जातियों को मजबूत करो'। इसी नारे पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) खड़ी हुई। परिणामस्वरूप डा. आंबेडकर द्वारा स्थापित जाति-व्यवस्था विरोधी आंदोलन की अवधारणा को मायावती ने शुद्ध जातिवादी अवधारणा में बदल दिया। इतना ही नहीं, गौतम बुद्ध द्वारा दी गई 'बहुजन हिताय' की अवधारणा को चकनाचूर करके उन्होंने 'सर्वजन हिताय' का नारा दिया, जिसका व्यावहारिक रूप सभी जातियों के गठबंधन के अलावा कुछ भी नहीं था। परिणामस्वरूप दलितों की विभिन्न जातियों के साथ-साथ ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के अलग-अलग सम्मेलनों की बसपा ने भरमार कर दी, जिससे हर जाति का दंभी गौरव खूब पनपने लगा।

ब्राह्मण सम्मेलनों के दौरान बसपा के मंचों पर हवन कुंड खोदे जाने लगे और वैदिक मंत्रों के बीच ब्राह्मणत्व का प्रतीक परशुराम का फरसा (वह भी चांदी का) मायावती को भेंट किया जाने लगा। इस दौरान दलित बड़े गर्व के साथ नारा लगाते थे- 'हाथी नहीं, गणेश हैं, ब्रह्मा-विष्णु-महेश हैं'। मायावती हर मंच से दावा करने लगीं कि ब्राह्मण हाशिये पर चले गए हैं, इसलिए वे उनका खोया हुआ गौरव वापस दिलाएंगी। वे इस तथ्य को जरा भी समझ नहीं पाईं कि ब्राह्मण कभी भी हाशिये पर नहीं जाते हैं। उनका सबसे बड़ा हथियार धर्म और ईश्वर है। इन्हीं हथियारों के बल पर ब्राह्मणों ने हमेशा समाज की बागडोर अपने हाथ में रखी।

इससे पहले मायावती तीन बार भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बनीं और गठबंधन की सरकार चलाई। इतना ही नहीं, भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मायावती विश्व हिंदू परिषद के त्रिशूल दीक्षा समारोह में भी शामिल हुईं। पर जब वे मोदी का प्रचार करने गुजरात गईं, तो उन्होंने धार्मिक उन्माद पर खुलेआम ठप्पा लगा दिया। दलित सत्ता के नारे के साथ मायावती ने जातीय सत्ता की प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया। इस जातीय सत्ता की होड़ में मंडलवादियों ने शामिल होकर धर्म के स्तंभों को और मजबूत किया।

अगर राजनीति में धर्म का इस्तेमाल धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध है, तो धर्म से उत्पन्न जाति का इस्तेमाल कैसे धर्म-निरपेक्ष हो सकता है? इसलिए धर्म का राजनीति में इस्तेमाल जितना खतरनाक है, जाति का इस्तेमाल उससे कम खतरनाक नहीं है। इस तथ्य को न कभी मायावती समझ पाईं और न ही मंडलवादी। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव और नीतीश कुमार आदि सब ने जातिवादी राजनीति के माध्यम से धर्म की राजनीति को मजबूत किया।

आज नरेंद्र मोदी जो छप्पन इंच का सीना तान कर घूम रहे हैं, उसकी पृष्ठभूमि में जातिवादी राजनीति रही है। उक्त सारे नेताओं द्वारा जाति के साथ-साथ मुसलिम वोटों का अपने पक्ष में ध्रुवीकरण करने के प्रयास से आम हिंदू नाराज होकर पूरी तरह भाजपा की तरफ चला गया। इसलिए संघ परिवार जिसकी वकालत बरसों से कर रहा था, उसमें वह पूर्णतः सफल रहा। भाजपा ने धर्म और जाति, दोनों का इस्तेमाल बड़ी रणनीति के साथ किया, जिसके पीछे वह चालाकी से 'विकास' की बात करके जनता को भ्रमित करने में सफल रही, जबकि असली मुद्दा धार्मिक ध्रुवीकरण का ही था।

मायावती ने डा. आंबेडकर की मूर्तियों और पार्कों की आड़ में दलितों को उनके रास्ते से भटकाने का काम बड़ी सफलता से किया। डा. आंबेडकर ने दलितों को सामाजिक और धार्मिक भेदभाव से मुक्ति दिलाने के लिए एक दोहरी रणनीति अपनाई थी। एक तरफ उन्होंने जाति-व्यवस्था विरोधी आंदोलन का सूत्रपात करके 'मनुस्मृति' को जलाया था और दूसरी तरफ जातिवाद को स्थापित करने वाले वैदिक ब्राह्मण धर्म के विकल्प के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाया था। मायावती डा. आंबेडकर की दोनों रणनीतियों को दरकिनार करके जातिवादी राजनीति के चंगुल में फंसती चली गईं।

एक बार कांशीराम ने घोषणा की थी कि वे डा. आंबेडकर से कहीं ज्यादा लोगों के साथ, यानी बीस लाख से अधिक लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे, पर स्वास्थ्य की समस्या के कारण वे ऐसा नहीं कर पाए। बाद में मायावती ने कहा कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने से सामाजिक सद्भावना के बिगड़ने की संभावना है, इसलिए जब वे प्रधानमंत्री बन जाएंगी, तो बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगी। जाहिर है, जब उन्होंने उक्त बातें कहीं, उस समय मायावती भाजपा के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही थीं।

डा. आंबेडकर के दर्शन के बारे में एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वे भारत के लिए द्वि-दलीय प्रणाली की वकालत करते थे, इसलिए वे दलित नाम से कोई पार्टी नहीं चलाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को प्रस्तावित किया। कांग्रेस का यही विकल्प उन्होंने प्रस्तुत किया था। पर एक बात उन्होंने जोर देकर कही थी कि दलितों को आरएसएस और हिंदू महासभा (वर्तमान विश्व हिंदू परिषद) जैसे संगठनों के साथ कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए।

संघ ने 1951 में जनसंघ की स्थापना की थी, पर आंबेडकर के समय में उसका प्रभाव नगण्य था। इसीलिए सीधे-सीधे उन्होंने संघ से किसी भी तरह का समझौता करने से दलितों को मना किया था। मायावती ने डा. आंबेडकर के हर कदम को नजरअंदाज करके संघ-परिवार का हाथ मजबूत किया। डा. आंबेडकर का जनतंत्र में अटूट विश्वास था, जिसकी झलक भारत के संविधान में साफ तौर पर मिलती है। उनका मानना था कि जाति-व्यवस्था एक तरह से तानाशाही वाली व्यवस्था थी, जिसके चलते दलित हर तरह के मानवीय अधिकारों से वंचित रहे। इसलिए जनतांत्रिक प्रणाली को वे दलितों के लिए सर्वोत्तम प्रणाली समझते थे।

पर सारी जातिवादी पार्टियां अपनी ही जाति के लोगों को हमेशा जनतांत्रिक अधिकारों से वंचित करती रही हैं। ऐसी पार्टी के नेताओं में मायावती का नाम सबसे ऊपर आता है। यहां तक कि बैठकों के दौरान न सिर्फ मायावती कुर्सी पर बैठा करती थीं और बाकी नेता जमीन पर बैठते थे। विधानसभा हो या संसद, उनके डर से कोई पार्टी विधायक या सांसद कुछ भी बोलने से डरता था। उनका व्यवहार एकदम सामंती हो गया था। उन्हें आम सभाओं में चांदी-सोने के ताज पहनाए जाते थे और उनके हर जन्म दिवस पर लाखों रुपए की भारी-भरकम माला भी पहनाई जाती थी। 1951 में मुंबई के दलितों ने बड़ी मुश्किल से 254 रुपए की एक थैली डा. आंबेडकर को उनके जन्मदिन पर भेंट की थी, जिस पर नाराज होकर उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर कहीं भी ऐसा दोबारा किया तो वे ऐसे समारोहों का बहिष्कार करेंगे।

पिछली दफा राज्यसभा का परचा दाखिल करते हुए मायावती ने आमदनी वाले कालम में एक सौ तेईस करोड़ रुपए की संपत्ति दिखाई थी। हकीकत यह थी कि मायावती के गैर-जनतांत्रिक व्यवहार के चलते बसपा में भ्रष्ट और अपराधी तत्त्वों की भरमार हो गई थी, जिसके कारण पूरा दलित समाज न सिर्फ बदनाम हुआ, बल्कि इससे दलित विरोधी भावनाएं भी समाज में खूब विकसित हुईं। एक तरह से मायावती दलित वोटों का व्यापार करने लगी थीं। पिछले अनेक वर्षों में चमार और जाटव समाज के लोग उत्तर प्रदेश में भेड़ की तरह मायावती के पीछे चलने लगे थे। इसलिए वे भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को चुन कर विधानसभा और संसद में भेजने लगे थे।

बाबा साहेब आंबेडकर ने संविधान सभा में बोलते हुए एक बार कहा था, 'धर्म में नायक पूजा किसी को मुक्ति प्रदान कर सकती है, पर राजनीति में नायक पूजा निश्चित रूप से तानाशाही की ओर ले जाएगी।' मायावती के संदर्भ में यह शत-प्रतिशत सही सिद्ध हुआ। राजा-रानियों की तरह मायावती ने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करते हुए प्रेस सम्मेलन में कहा था, 'मेरा उत्तराधिकारी चमार जाति का ही होगा, जिसका नाम मैंने एक लिफाफे में बंद कर दिया है। यह लिफाफा मेरी मृत्यु के बाद खोला जाएगा।' इससे एक बात साफ हो गई कि मायावती के रहते कोई अन्य दलित नेता नहीं बन सकता था।

उनके द्वारा बार-बार चमार जाति के उल्लेख से दलित की गैर-चमार जातियां बसपा से कटती चली गईं और उनमें से अधिकतर या तो भाजपा के साथ हो गईं या मुलायम सिंह यादव के साथ चली गईं। उत्तराधिकारी की घोषणा के बाद एक रोचक घटना हुई। मीडिया वालों ने अंदाजवश आजमगढ़ के राजाराम के रूप में उत्तराधिकारी की पहचान कर ली। परिणामस्वरूप मायावती ने अविलंब राजाराम को पार्टी से बर्खास्त कर दिया।

जब मायावती सामाजिक अभियांत्रिकी (सोशल इंजीनियरी) के नाम पर ब्राह्मणों को सतीश मिश्रा के माध्यम से अपनी तरफ खींचने का अभियान चला रही थीं तो दलितों के विरुद्ध उसका दूरगामी प्रभाव पड़ा। इससे पहले चुनावी राजनीति में ही सही, सारी पार्टियां दलितों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती थीं और उनके लिए तरह-तरह के वादे भी किया करती थीं, जिसका परिणाम अनेक अवसरों पर काफी सकारात्मक भी हुआ करता था। इसलिए दलित हमेशा एक दबाव समूह का काम करते थे। पर मायावती उस तथाकथित सामाजिक अभियांत्रिकी के चलते हर पार्टी के लिए ब्राह्मण खुद दबाव समूह के लिए दलितों को हाशिये पर डाल दिए। परिणामस्वरूप मायावती के चक्कर में दलित हर पार्टी के लिए दुश्मन बन गए। अब उनके कल्याण के लिए कोई भी पार्टी तत्पर नहीं दिखाई पड़ती। सच ही कहा गया है, 'माया मिली न राम।'

मायावती के एक अन्य दलित-विरोधी फैसले का दूरगामी प्रभाव पड़ा। किसी गैर-दलित मुख्यमंत्री की कभी हिम्मत नहीं पड़ी कि वह 'दलित अत्याचार विरोधी अधिनियम' से छेड़छाड़ करे। पर मायावती जब भाजपा के साथ संयुक्त सरकार चला रही थी, तो उन्होंने गैर-दलितों को खुश करने के लिए उपरोक्त अधिनियम में संशोधन करके यह प्रावधान कर दिया कि दलित महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे अपराधों को पुलिस तब तक दर्ज न करे, जब तक कि डाक्टर प्रमाणित न कर दे कि सही मायने में बलात्कार हुआ है। मायावती के इस आदेश का परिणाम यह हुआ कि दलितों पर तरह-तरह के अत्याचार होते रहे, पर पुलिस अधिकतर मामलों में आज भी केस दर्ज नहीं करती है।

इस बार लोकसभा चुनावों में जब बसपा का सफाया हो गया, तो मायावती ने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया। हकीकत तो यह है कि मायावती अपनी व्यक्तिगत सत्ता के लिए लगातार जातिवादी नीतियां अपनाती रही हैं, जिससे दलित निरंतर सबसे कटते चले गए। पिछले 25 सालों के अनुभव से पता चलता है कि अब देश को जातिवादी पार्टियों की जरूरत नहीं है, बल्कि सबके सहयोग से जाति-व्यवस्था विरोधी एक मोर्चे की आवश्यकता है, अन्यथा जातियां मजबूत होती रहेंगी, जिससे धर्म की राजनीति को आक्सीजन मिलता रहेगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान डा. आंबेडकर ने गांधीजी से कहा था, 'स्वतंत्रता आंदोलन में सारा देश एक तरफ है, पर जाति-व्यवस्था विरोधी आंदोलन सारे देश के खिलाफ है, इसलिए यह काम बहुत मुश्किल है।' उम्मीद है, दलित इतिहास से कुछ सीख अवश्य लेंगे।

(जनसत्ता से साभार)

बाबा साहेब ने अनुच्छेद 370 का किया था विरोध

डॉ. संतोष कुमार तिवारी

जिस प्रकार से विश्व की राजनीति में कार्ल मार्क्स ने मजदूरों के पक्ष में एक अमिट छाप छोड़ी है, उसी प्रकार से आधुनिक भारत के इतिहास में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने पूरे राष्ट्र में वंचित समाज के पक्ष में सामाजिक और राजनीतिक चेतना को जागृत किया है।

आज भारत का जन साधारण उनको सिर्फ आरक्षण नीति के प्रवर्तक के तौर पर जानता है। आम आदमी यह भी जानता है कि वह हमारी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। इस तरह वह भारतीय संविधान के निर्माता माने जाते हैं।

अम्बेडकर ने महिलाओं को पुरुषों को संपत्ति में बराबर का अधिकार दिलाने के लिए भी बहुत कुछ किया था। इसके अलावा इस लेख का दूसरा उद्देश्य यह बताना है कि अम्बेडकर संविधान के अनुच्छेद 370 के विरुद्ध भी थे।

हालांकि अम्बेडकर महात्मा गांधी के प्रखर विरोधी थे, तब भी कांग्रेस पार्टी ने सन् 1947 में उन्हें देश का पहला विधि मंत्री बनाया था। महात्मा गांधी ने उनको विधि मंत्री बनाए जाने का विरोध नहीं किया था।

विधि मंत्री के तौर पर उन्होंने हिंदू कोड बिल तय किया था, जिसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति में पुरुषों के बराबर हकदार बनाया गया था। यह कदम उस समय इतना क्रांतिकारी था कि तत्कालीन पंडित नेहरु की सरकार इसे कानून का दर्जा नहीं दिलवा पाई। इस कारण इन्होंने वर्ष 1951 में विधि मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हिंदू कोड बिल सभी हिंदुओं के लिए था, न कि सिर्फ वंचितों के लिए। बाद में लोकसभा का चुनाव हारने के बाद बाबा साहेब वर्ष 1952 में राज्यसभा के सदस्य बने और जीवनपर्यन्त इस सदस्यता को बरकरार रखा। राज्यसभा की सदस्यता छह वर्ष के लिए होती है। बाबा साहब की मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुई थी।

विधि मंत्री पद से उनके इस्तीफे के बाद नेहरू सरकार हिंदू कोड बिल को टुकड़ों-टुकड़ों में संसद में पारित करा पाई। टुकड़ों-टुकड़ों में बने ये कानून थे :

- हिंदू विवाह अधिनियम 1955
- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956
- हिंदू अल्पवयस्कता और संरक्षता अधिनियम 1956
- हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम 1956

बाबा साहेब अम्बेडकर चाहते थे कि सभी भारतीयों के लिए एक जैसा यूनीफार्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) बने। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया था। परंतु आज तक वोट की राजनीति के कारण उनका यह सपना पूरा नहीं हो सका।

इंग्लैंड में तो समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन वहां के मुस्लिम तो उसका विरोध नहीं करते हैं। वर्ष 1982 में इस लेख का लेखक लंदन के रीजेंट पार्क स्थित यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद के इमाम से मिला था। वह इमाम सऊदी अरब के थे और कभी भारत में लखनऊ में भी रहे थे। उनसे इस लेखक ने पूछा था कि इंग्लैंड में आप लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करने की मांग क्यों नहीं करते हैं? इमाम ने अपने जवाब में कहा था कि इंग्लैंड में अभी हमारी आबादी कम है, जब वह बढ़ जाएगी तब यह मांग की जाएगी।

वर्ष 1982 में मुझे (लेखक) पत्रकारिता की शिक्षा ग्रहण करने के लिए ब्रिटिश स्कालरशिप मिली थी। इसलिए मैं लन्दन में था। ये बातें इस लेखक ने इंग्लैंड से लौटकर अपने यात्रा वृत्तांत में लखनऊ और इलाहाबाद से निकलने वाले दैनिक अखबार अमृत प्रभात में लिखी भी थीं। अमृत प्रभात कोलकाता के अमृत बाजार पत्रिका समूह का अखबार था।

जहां तक संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रश्न है, बाबा साहब कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने के पक्ष में नहीं थे। जिस दिन संविधान सभा में 370 पर चर्चा होनी थी, तो अम्बेडकर ने उसमें हिस्सा नहीं लिया था। हालांकि वह अन्य चर्चाओं में बोले थे। अनुच्छेद 370 के पक्ष में सभी दलीलें अय्यंगर ने दी थीं। ये बातें विकिपीडिया में बलराज मधोक को उद्धृत करते हुए कही गई हैं।

बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा था कि यह अनुच्छेद 370 सिर्फ एक अस्थाई प्रावधान है। हालांकि वोट की राजनीति के चलते यह उसी तरह से एक किस्म का स्थाई प्रावधान हो गया है।

आज बाबा साहेब के समर्थक भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों में हैं। इनमें कांग्रेस पार्टी, भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टियां भी शामिल हैं। इस लेख का उद्देश्य सभी दलों के बाबा साहब समर्थक सांसदों को यह याद दिलाना है कि वे देश में समान नागरिक संहिता (कामन सिविल कोड) लागू कराने के लिए और अनुच्छेद 370 हटवाने के लिए कार्य करें। बाबा साहब के जन्मदिन 14 अप्रैल को उनकी प्रतिमा पर सिर्फ फूल माला चढ़ाना ही काफी नहीं है।

(लेखक झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रांची में जनसंचार केंद्र के अध्यक्ष हैं)

(साभार - पांचजन्य)

बसपा का दलित जनाधार खिसका : डॉ0 उदित राज

नई दिल्ली, 17 मई, 2014.

डॉ0 उदित राज, सांसद एवं विशेष आमंत्रित सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, भाजपा ने कहा कि बसपा अध्यक्ष सुश्री मायावती की बौखलाहट आज उनकी प्रेस वार्ता में देखी गयी। उन्होंने बार-बार कहा कि बसपा का दलित वोट रत्ती भर भी खिसका नहीं, जो पूरी तरह से असत्य है। इन्होंने अपने खोए हुए जनाधार को छुपाने के लिए चुनाव परिणाम को गणित की तरह आकड़ा पेश करने की कोशिश किया है लेकिन वह भी नहीं कर पायीं। उ0 प्र0 में दलित की आबादी लगभग 23 प्रतिशत है और वोट इनको 20 प्रतिशत से भी कम मिले हैं। उन्होंने कहा कि उनको मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग एवं सवर्ण वोट इस बार नहीं मिले जबकि यह पूरी तरह से गलत है। सच्चाई यह है इस बार भाजपा को दलित वोट ज्यादा मिले और ऐसा तमाम सर्वेक्षण भी बता रहे हैं। अभी आंकड़ों का विश्लेषण चल रहा है और जल्दी ही पूरे तथ्यों के साथ इसकी पुष्टि हो जाएगी। बसपा ने इस बार उ0प्र0 में 21 मजबूत ब्राह्मणों को टिकट दिया था, जिनके अपने अच्छे-खासे जनाधार थे। इसी तरह से अन्य स्थानों पर भी जातीय समीकरण के आधार पर टिकट वितरित किए थे, जिनका अपना जातीय एवं व्यक्तिगत् जनाधार अच्छा-खासा है। अगर इस समीकरण पर टिकट न दिया होता या गैर दलित प्रत्याशी के वोट न मिले होते तो बसपा को लगभग 10 प्रतिशत वोट ही मिलते।

डॉ0 उदित राज ने कहा कि देश के तमाम दबे-कुचले एवं दलितों को धन्यवाद कि उन्होंने जाति के ऊपर उठकर भाजपा को विकास और सभी वर्गों की भागीदारी के लिए वोट देकर नरेन्द्र भाई मोदी को पधानमंत्री बनाने में सहयोग किया है।

सत्ता में दलित भागीदारी से ही राष्ट्र निर्माण संभव है : डॉ. उदित राज

उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से डॉ. उदित राज का सांसद चुने जाने के बारे में तथ्य पेश कर रहे हैं पद्मेंदर

डॉ. उदित राज अपने जीवन के महत्वपूर्ण 17 साल पूरे भारतीय दलित समाज को शैक्षणिक, सामाजिक एवं राजनैतिक भागीदारी के लिए समर्पित कर दिया। जब-जब भारतीय दलित समाज की अस्मिता पर किसी ने कुठाराघात किया, चाहे दलित उत्पीड़न या दलित महिला के दुराचार का मामला हो या फिर संवैधानिक भागीदारी या जातिवाद, भ्रष्टाचार, आदि मिटाने का मामला हो, डॉ. उदित राज निरंतर संघर्ष करते रहे। वह अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ, लार्ड बुद्धा क्लब, इंडियन जस्टिस पार्टी का निर्माण कर संघर्ष करते रहे। संघर्ष के दौरान भारत में समानता हेतु लाखों लोगों को बौद्ध बनाया, एससी/एसटी परिसंघ के माध्यम से आरक्षण बचाकर दलित समाज को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से मजबूत किया। समय की मांग यह कहती रही कि डॉ. उदित राज का संसद में जाना बहुत जरूरी है। बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर दलित अधिकारों को लेकर 1942 में दलित महासंघ बनाए, लेकिन दलित अधिकार तभी मिल पाया जब डॉ. अंबेडकर कांग्रेस के मंत्रिमंडल में जाकर दलित अधिकार कानून बनाए। इसलिए डॉ. अंबेडकर द्वारा दिए गए अधिकारों को सुरक्षित करने हेतु डॉ. उदित राज को संसद में जाना पड़ा है।

लगभग सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पार्टियां समाज को वर्ग (जाति) एवं क्षेत्रवाद में बांटकर भारत को खंडित किया है। लगभग 67 वर्षों से देश महंगाई, भ्रष्टाचार एवं आतंक आदि समस्याओं से जूझ रहा है जिसके लिए कांग्रेस सबसे ज्यादा दोषी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एवं आएसएस के बड़े नेताओं को राष्ट्र निर्माण की चिंता बढ़ती चली गयी। भारत को विकासशील देश बनाने की चिंता हुई, देश को कैसे उपरोक्त समस्याओं से निजात दिलाया जाए, इस पर चिंतन होने लगी। इन सारी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी देश के सभी वर्गों-धर्मों के प्रतिनिधि से बातकर सबको मिलकर राष्ट्र निर्माण की कल्पना की। इसी दौरान दलितों के मसीहा डॉ. अंबेडकर के बाद दलित समाज के चिंतक डॉ. उदित राज से संपर्क भाजपा नेताओं ने किया। डॉ. उदित राज ने साफ तौर पर यह कहा कि देश तभी विकसित देश बन सकेगा एवं उपरोक्त समस्याओं से निजात पा सकेगा जब दलितों, पिछड़ों एवं आदिवासियों को सभी क्षेत्रों में भागीदारी मिलेगी। देश में थोड़े लोग खाना खाए और अधिकतर लोग भूखे सोएं, 1/4 देश में उजाला हो जबकि 3/4 भाग में लोग अंधेरे में रहे, 1/4 लोगों के तन पर कपड़ा रहे और 3/4 लोग नंगे रहे, 1/4 लोगों को दवा मिले वहीं 3/4 लोग दवा बिना ही मौत को गले लगा लें, 1/4 लोगों को रोजगार मिले तो 3/4 लोग नौकरी के लिए दर-दर भटकते रहे, इस प्रकार राष्ट्र कभी खुशहाल नहीं हो सकता और न ही नए राष्ट्र का निर्माण हो सकता है।

भारतीय जनता पार्टी एवं आरएसएस के नेताओं में ऐतिहासिक बदलाव आया तथा डॉ. उदित राज की शर्तों को मानकर उन्हें सांसद बनाने के रास्ते को मजबूत कर राष्ट्र निर्माण का हिस्सा बनाया। डॉ. उदित राज को जिताने के लिए भारत के सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर हजारों की संख्या में चुनाव प्रचार में लगे रहे और अंततः वे उत्तर-पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद में पहुंचने में सफलता प्राप्त किए।

मैं अपनी ओर से उत्तर-पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के कार्यकर्ताओं एवं देश के कोने-कोने से प्रचार करने आए समर्थकों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशि:

पांच वर्ष : 600 रुपए

एक वर्ष : 150 रुपए

दलितों का मुख्यधारा में आने का समय

डॉ. उदित राज

पहली लोकसभा का चुनाव सन् 1952 में हुआ था। उस समय दलित राजनीति खास नहीं थी। दलितों एवं आदिवासियों में वोट की कीमत का एहसास नाममात्र था। हालांकि उस समय बाबा भीमराव डॉ0 अंबेडकर जीवित थे फिर भी इस समाज में जागृति का बड़ा अभाव था। डॉ. अंबेडकर स्वयं चुनाव हारे। समयांतराल जागृति आती गयी और दलित राजनीति का प्रादुर्भाव होता गया। महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अस्तित्व में आयी लेकिन उसकी भी सफलता आंशिक ही रही। सन् 1960 के दशक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित-मुस्लिम गठजोड़ आंशिक रूप से सफल रहा। सन् 1993 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन ने दलित राजनीति का एक नया युग शुरू किया। यह गठबंधन बहुत दिनों तक नहीं चल पाया। बहुजन समाज पार्टी ने एक नया प्रयोग किया और उन्हें उम्मीदवार बनाया गया यह सोच-समझकर कि उसका अपना वोट इतना तो है कि दलित वोट यदि मिल जाए तो जीत की स्थिति में पहुंचा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में दलित और सवर्ण समीकरण ने 2007 में एक बड़ी सफलता दी लेकिन वह इस लोकसभा चुनाव में ढ़ह गया। आज प्रश्न यह है कि क्या अकेले दलित वोटों से मुख्यधारा में आया जा सकता है? बिना मुख्यधारा में आए क्या पक्ष में नीतियां बनवायी जा सकती है?

श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से राजनैतिक ध्रुवीकरण सोलहवीं लोकसभा चुनाव में हुआ उससे न केवल क्षेत्रीय दल प्रभावित हुए बल्कि दलित राजनीति भी। मुझे भी यह अनुमान नहीं था कि इस तरह से दलित राजनीति को झटका लगेगा। इतनी समझ जरूर आ गयी थी कि मुख्यधारा की पार्टी में बिना जुड़े दलितों, आदिवासियों एवं वंचितों के लिए नीतियां बनायी नहीं जा सकती है। मात्र पहचान बनाना अब काफी नहीं है बल्कि भागीदारी चाहिए। भागीदारी से देश का सर्वांगीण विकास होगा और इससे खुशहाली और राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलेगी। शुरू में मेरे साथियों को झटका सा लगा जब ऐसा प्रस्ताव रखा गया लेकिन अंततः उन्हें समझाने में कामयाब रहा और अंत में 24 फरवरी को भाजपा में शामिल हो गया। यह मंथन अक्टूबर, 2013 से ही चल रहा था और संतुष्टि की बात यह है कि चुनाव के दौरान पूरे देश में मेरे समर्थकों का प्रयास अच्छा रहा। दलितों ने इस बार भाजपा को प्रचंड समर्थन दिया। इनके झुकाव को बहुत सरलता से नहीं देखना चाहिए बल्कि एक आशा और विश्वास इसके पीछे है। नरेंद्र भाई मोदी ने 20 मई को संसद में सही कहा कि लोगों ने वोट आशा और विश्वास को दिया है।

दलित राजनीति अब इन्हें थका रही है कि केवल मान-सम्मान की बात कहने से भागीदारी और आत्मनिर्भरता नहीं मिलने वाली है। दलित राजनीति का मुख्य प्रतीक बनी मायावती दलितों को वह भी नहीं दे रही हैं जिसके लिए वे विशेष रूप से जुड़े। दलित बुद्धिजीवियों में भारी निराशा है कि आरक्षण की वजह से जो भागीदारी पहले मिल रही थी उसमें भी कटौती होती चली जा रही है। नई आर्थिक नीति के कारण तमाम रोजगार-व्यवसाय के अवसर पैदा हो रहे हैं लेकिन दलितों-आदिवासियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में उदासीनता आई कि इनका वोट क्षेत्रीय दलों में जाने लगा तो ऐसी स्थिति में इनके लिए कुछ करने की इच्छाशक्ति कम हुई। इस बार के लोकसभा के चुनाव में दलित वोट भारतीय जनता पार्टी को अच्छा मिला और इसका फल उन्हें जरूर मिलना चाहिए। गत् 2 मार्च की लखनऊ रैली में नरेंद्र भाई मोदी ने कहा कि आने वाला दशक पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों एवं वंचितों का होगा और इसका असर व्यापक हुआ।

बसपा को उत्तर प्रदेश में 19.6 प्रतिशत वोट मिला जबकि दलितों की आबादी 22 प्रतिशत है। मायावती ने 17 मई को कहा कि उनका दलित वोट खिसका नहीं है जो कि झूठ है। ये उन्हीं को टिकट देती है जिनकी जाति का अच्छा-खासा वोट होता है। बसपा के ताकतवर उम्मीदवारों का वोट फिर कहां गया? सच्चाई यह है कि इस बार अच्छा-खासा दलित वोट भाजपा में गया है। मायावती मनोवैज्ञानिक युद्ध के माध्यम से दलितों को भ्रमित करके अपना जनाधार बनाये रखना चाहती है। 20 मई को जिस तरह से संसद में नरेंद्र भाई मोदी ने दलितों और गरीबों के उत्थान की बात कही उससे यह स्पष्ट होता जा रहा है कि उनकी सरकार इन्हें भागीदारी देगी। ऐसा होना संभव प्रतीत होता जा रहा है तो दलित मुख्यधारा की पार्टी भारतीय जनता पार्टी में जरूर आएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वह छाप नहीं रह गयी है कि यह सवर्णों की पार्टी है। मेरा जिस तरह से भाजपा ने स्वागत किया है उसका भी असर देश के दलितों में है कि यदि हम अपने समाज को जोड़ते हैं तो पार्टी का दिल छोटा नहीं है और वह पूरा सम्मान देगी। दूसरी सबसे अच्छी बात यह हुयी कि सवर्ण और दलित के बीच जो खाई बढ़ती जा रही थी वह कम हुयी है और मुझे विश्वास है कि आगे और अच्छा होगा। जिस पार्टी का अंतिम लक्ष्य यह हो कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बने तो यह स्वाभाविक है कि वह हर वर्ग को मान-सम्मान और भागीदारी दे। राष्ट्रीयता और कला-संस्कृति का बचाव तभी हो सकता है जब राजनैतिक सत्ता पर कब्जा हो। भाजपा के लिए यह सुनहरा अवसर है कि दलितों को भागीदारी देकर न केवल राजनैतिक बल्कि सामाजिक जनाधार को मजबूत कर ले।

उत्तर-पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से डॉ. उदित राज की शानदार जीत

सी. एल. मौर्य

16 मई, 2014 को जैसे ही 16वीं लोक सभा चुनाव के परिणामों की घोषणा हुई और भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए को 335 सीटों पर शानदार विजय मिली, इससे जहां पूरे देश में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ वहीं विशेष रूप से डॉ0 उदित राज को नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोक सभा सीट से विजय पर पूरे देश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के चेहरे इस आशा के साथ खिल उठे कि अब इस समाज की आवाज बुलंद करने वाले व्यक्ति, डॉ0 उदित राज, संसद में पहुंच गए हैं।

डॉ0 उदित राज का जन्म इलाहाबाद के एक छोटे से गांव राम नगर में हुआ था। 12वीं तक की पढ़ाई स्थानीय स्कूल - कॉलेज में पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा हेतु दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। इन्होंने बी.ए. एवं एम.ए. की डिग्री के पश्चात् कानून की पढ़ाई भी की और इन्हें डॉक्टरेट ऑफ ह्यूमैनिटीज की उपाधि भी प्राप्त है। 1988 में इनका चयन भारतीय राजस्व सेवा में हुआ और ट्रेनिंग के उपरांत गाजियाबाद में आयकर विभाग में सहायक आयुक्त के पद पर आसीन हुए। इसके बाद इनकी पदोन्नति उपायुक्त आयकर, संयुक्त आयुक्त आयकर एवं अतिरिक्त आयुक्त आयकर के पद पर हुई।

घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण डॉ0 उदित राज को सरकारी सेवा में जाना पड़ा लेकिन हमेशा ही दलितों, गरीबों व वंचितों के लिए कुछ कर गुजरने की टीस मन में उठती रहती थी। सरकारी सेवा में रहते हुए इन्होंने आयकर विभाग के अंदर इन्कम टैक्स एस. सी./एस.टी. इम्प्लाइज फेडरेशन का गठन किया। 1997 में तत्कालीन तथाकथित सामाजिक न्याय की सरकार द्वारा पांच आरक्षण विरोधी आदेश जारी किए गए जिससे तमाम विभागों में कार्यरत् अधिकारियों व कर्मचारियों में त्राहि-त्राहि मच गयी और डॉ0 उदित राज जी से यह देखा नहीं गया। उन्होंने तमाम विभागों में गठित समितियों की बैठक बुलायी और उन्हें सम्बोधित करते हुए कहा कि अपने-अपने तरीके से संघर्ष करने और आंदोलन चलाने से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि संगठित होकर न आंदोलन करें। देशव्यापी आंदोलन चलाने के लिए पूरे देश के तमाम विभागों में गठित संस्थाओं को मिलाकर 'अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ' बना और सर्वसम्मति से डॉ0 उदित राज को इसका राष्ट्रीय चेयरमैन बनाया गया। पूरे देश में आंदोलन चला और 1998, 1999, 2000 में राम लीला मैदान, नई दिल्ली में बड़ी-बड़ी रैलियां आरक्षण विरोधी आदेशों की वापिसी के लिए की गयीं। 11 दिसंबर, 2000 को हुई रैली को तो मीडिया ने सदी की सबसे बड़ी रैलियों में से एक बताया (हिन्दुस्तान अखबार के अनुसार)। 2001 में जातिविहीन समाज की स्थापना के लिए लाखो अनुयायियों के साथ डॉ0 उदित राज जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसके बाद से अभी तक अनुसूचित जाति/ जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ का आंदोलन दलित उत्थान के लिए जारी है। डॉ0 उदित राज के नेतृत्व में चले इस आंदोलन की वजह से श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने तीन संवैधानिक संशोधन किए और अनुसूचित जाति/जन जाति का आरक्षण बच सका।

सामाजिक संगठनों के अपने दायरे होते हैं, इसीलिए डॉ0 उदित राज ने दलितोत्थान के लिए राजनैतिक मंच का सहारा लेने का निर्णय किया। उन्होंने कई विभिन्न पार्टियों के दलित सांसदों को एक साथ बैठाकर आग्रह किया कि वे दलित हितों की बात संसद में क्यों नहीं उठाते हैं? सांसदों ने दलितों के हित में संसद से नीतियां बनाने का वायदा भी किया लेकिन वे ज्यादा कुछ नहीं कर सके। इसी के मद्देनजर उन्होंने 2003 में राजनैतिक पार्टी 'इंडियन जस्टिस पार्टी' की स्थापना कर दी। इंडियन जस्टिस पार्टी के बनने से अपने आपको दलितों की हितैषी बताने वाली बसपा जैसी पार्टियों में हड़कंप तो मचा लेकिन धनाभाव के कारण राजनैतिक पार्टी चलाना मुश्किल सा दिखने लगा तो पूरा समय पुनः अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ को देना शुरू कर दिया लेकिन बार-बार यही आवश्यकता महसूस होती रही कि जब तक संसद के अंदर न पहुंचे अजा/जजा वर्ग के लिए ज्यादा कुछ खास नहीं किया जा सकता तो अन्य राजनैतिक संभावनाओं पर विचार शुरू हुआ।

डॉ0 उदित राज ने रैलियों के माध्यम से कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाया कि दलितों को निजी क्षेत्र में आरक्षण दे और पदोन्नति में आरक्षण की बहाली के साथ-साथ आरक्षण का उल्लंघन करने वालों पर कड़े दंड का प्रावधान करे। लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस पर कागजी कार्यवाही एवं बैठकों के अलावा कुछ नहीं किया। डॉ0 उदित राज ने देखा कि अभी तक के संघर्ष दलितों को सबसे अधिक लाभ श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतश्त्ववाली भाजपा सरकार के शासन काल में ही सबसे अधिक दलितों हितों के काम हो सके चाहे वह संवैधानिक संशोधन के माध्यम से आरक्षण की बहाली का मामला हो अथवा बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की दिल्ली स्थित परिनिर्वाणभूमि के सम्मान की बात हो।

24 फरवरी, 2014 को डॉ0 उदित राज ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, श्री राजनाथ सिंह जी की मौजूदगी में भाजपा कार्यालय 11 अशोक रोड़, नई दिल्ली पर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी और तुरंत प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया और भाजपा की ओर से उत्तर पश्चिम दिल्ली से उम्मीदवार बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी की टीम के अलावा इन्हें संसद पहुंचाने के लिए देश के कोने से अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के नेता व कार्यकर्त्ता पहुंचकर चुनाव में सहयोग किए।

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:
Five years : Rs. 600/-
One year : Rs. 150/-

संत शिरोमणि गुरू रविदास

आनंद श्रीकृष्ण

संत शिरोमणि गुरू रविदास भारत वर्ष के सबसे महान संत माने जाते हैं। संत रविदास का जन्म 15 फरवरी, 1398 माघी पूर्णिमा को वाराणसी 'उप्र' के निकट मण्डुवाडीह में हुआ था। उनके पिता का नाम रघुराम और माता का नाम करमा देवी था। संत रविदास के जन्म और बाल काल के बारे में कई मत प्रचलित हैं। एक मत के अनुसार रघुराम और करमा देवी संतानहीन थे। अपने व्यवसाय के सिलसिले में रघुराम बहुत से स्थानों पर जाया करते थे। एक बार उन्हें मृगदाय ऋषिपतन 'सारनाथ' जाना पड़ा। यही वह स्थान है जहां बुद्धत्व प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था जिसे 'धम्मचक्र प्रवर्तन' के नाम से जाना जाता है। संयोगवश यहीं पर रघुराम की मुलाकात रैवतप्रज्ञ नाम के एक बौद्ध भिक्षु से हुई। भिक्षु बहुत भूखे थे। रघुराम और करमा देवी ने उन भिक्षु को खीर का भोजन दान दिया। खीर दान के बाद दोनों पति-पत्नी ने बड़ी विनम्रता के साथ भिक्षु से अपनी संतानहीनता की बात कही। भिक्षु ने आशीर्वाद देकर कहा कि उनके घर शीघ्र ही एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसके कारण उन दोनों का नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। भिक्षु का आशीर्वाद पाकर रघुराम और करमा देवी काफी आनंदित हुए। कुछ दिन के बाद करमा देवी गर्भवती हुई और माघ पूर्णिमा, दिन रविवार को ईस. 1398 के दिन रघुराम के घर में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। आगे चलकर यही बालक एक महान क्रांतिकारी समाज सुधारक और संत शिरोमणि गुरू रविदास के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चूंकि भिक्षु का नाम रैवतप्रज्ञ था इसलिए बालक का नाम ''रैवतदास'' रखा गया, जो आगे चलकर ''रैदास'' हो गया।

गुरू रविदास ने अपने पदों के माध्यम से समाज में फैले मिथ्याचार आडंबर और रुढ़िवादिता पर प्रहार किया। उन्होंने ब्राह्मण श्रेष्ठता को सशक्त चुनौती दी और समानता, भ्रातृत्व, स्नेह और प्रेम का संदेश फैलाया। संत कबीर संत रविदास को अपना बड़ा भाई मानते थे और उनके विचारों से बहुत गहरे तक प्रभावित थे। संत रविदास और संत कबीर ने तत्कालीन समाज में व्याप्त जातिवाद, शोषण, असमानता, बाह्य आडंबर, पाखंड और शोषणवादी रीति रिवाजों पर कड़ा प्रहार किया। गुरू रविदास का अधिकांश समय भारत के विभिन्न प्रदेशों के भ्रमण में ही बीता। संबंधित प्रदेशों की बोली भाषा के अनुरूप इन्हें विभिन्न नामों से ख्याति प्राप्त हुई जैसे-

पंजाब में रैदास, बंगाल में रुईदास, महाराष्ट्र में रोहिदास, राजस्थान में रायदास, गुजरात में रोहिदास अथवा रोहितास, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में रविदास। गुरु ग्रंथ साहिब में रविदास के उल्लेखित चालीस पदों में अधिकांशतया ''रैदास'' नाम का ही वर्णन आया है। कहीं-कहीं 'रविदास' नाम का भी उल्लेख मिलता है। गुरु रविदास से संबंधित अधिकांश ग्रंथों की रचना भी रविदास नाम से ही हुई है। वे खासकर उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत और मध्य भारत के एक सर्वमान्य संत थे। उन्होंने भ्रातृत्व की बात की और सभी के प्रति प्रेम व स्नेह व्यक्त किया। उन्होंने श्रमण संस्कृति अथवा अपनी आजीविका स्वयं अर्जित करने का संदेश प्रचारित किया।

सामाजिक क्रांति में योगदान

गुरु रविदास महान सामाजिक व धार्मिक क्रांतिकारी थे। उन्होंने अपने कार्यों द्वारा तत्कालीन भारत में सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया। उस समय ये माना जाता था कि सन्यासी जीवन 75 वर्ष की उम्र पार करने के बाद बिताया जाता है। लेकिन गुरु रविदास ने दुनिया को यह दिखा दिया कि गृहस्थ जीवन में भी मोक्ष संभव है।

संत रविदास का विवाह लोना नाम की एक सुंदर विदुषी से हुआ था। गुरु रविदास ने अपना प्रारंभिक जीवन एक गृहस्थ के रूप में बिताया। उन्हें एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम विजय दास था। पत्नी के देहांत के बाद संत रविदास पूरी तरह आध्यात्मिक जीवन की तरफ अग्रसर हुए और पूरा जीवन समाज सुधार में लगा दिया। गुरु रविदास ने आत्म-सम्मान, आत्मबल और आत्म-सहायता पर जोर दिया।

संत रविदास जी ने ब्राह्मण श्रेष्ठता को चुनौती दी और मुक्ति, भ्रातृत्व, समानता, प्रेम व स्नेह का संदेश दिया। गुरु रविदास ने न केवल मनुवाद के वर्चस्व को चुनौती दी बल्कि वे समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व व न्याय उनके सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्तंभ भी थे। संत गोरखनाथ ने भी संत रविदास को अपना गुरु माना। गुरु रविदास भारतवर्ष के कोने-कोने में गये और समानता, भ्रातृत्व व सार्वजनिक एकात्मता का संदेश फैलाने के लिए कार्य किया। वे समतावादी समाज की बात करते थे। बुद्ध की तरह उनकी दृष्टि भी ऐसे समाज की थी, जहां भूख, गरीबी और दरिद्रता न हो। गुरु रविदास कहते हैं :

ऐसा चाहूं राज मैं,
जहां मिलै सबन को अन्न।
छोट बड़ो सब सम बसै,
रैदास रहे प्रसन्न ।

'मैं ऐसा राज चाहता हूँ जिसमें सबको भर पेट अन्न मिले। मुझे तभी खुशी होगी, जब उच्च या निम्न जाति को भुलाकर सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाए।'

संत रविदास ने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की थी जहां कोई भूखा और गरीब नहीं होगा, रोगी और दुःखी नहीं होगा, असमानता और शोषण का अभाव होगा और लोगों में प्रेम और सौहार्द की भावना होगी। ऐसे राष्ट्र को संत रविदास ने बेगमपुरा नाम दिया था। संत रविदास ने जाति, रंग या नस्ल पर आधारित लोगों के अत्याचारों का विरोध किया। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, समानता, व भ्रातृत्व का संदेश फैलाते हुए संत रविदास ने यह भी कहा कि किसी मानव की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि कर्म से होती है। बुद्ध की तरह उन्होंने यह भी शिक्षा दी कि धम्म के मार्ग पर चलने वालों के लिए जाति, नस्ल, लिंग या स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। उनके कुछ पद हैं -

रविदास सुकरमन करन सो
नीच-ऊंच हो जाये,
करही कुकर्म ऊंच भी,
तो महा नीच कहलाय ।

'अच्छे कर्म करके निम्न जाति में जन्मा व्यक्ति भी उच्च हो जाता है। गलत काम करके उच्च जाति में जन्मा व्यक्ति भी निंदनीय अथवा निम्न हो जाता है।'

रविदास जन्म के कारने,
होत न कोई नीच,
नर कूं नीच करि डारि हैं,
ओछे करम की कीच ।

'जन्म से कोई ऊंचा-नीचा नहीं होता, केवल बुरे कर्म अर्थात् गलत कार्य ही मानव को ऊंचा-नीचा बनाते हैं।'

महिला सशक्तिकरण में योगदान

संत रविदास के समय के भारत में महिलाओं को सामान्यतया शिक्षा नहीं दी जाती थी। उनके समकालीन कवि तुलसी दास ने तो यहां तक लिखा है कि 'ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी''

लेकिन संत रविदास ने उस परंपरा को तोड़ा और अनेक महिलाओं को शिक्षा देकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी काम किया। उनकी प्रमुख महिला शिष्यों में मीराबाई व चितौड़ की रानी झालीबाई सहित अनेक राज कुमारियाँ शामिल थी। मीराबाई ने अपने पदों में कहा है कि 'गुरु मिल्या रविदास जी'। मीराबाई पहले अनेकों संतों के पास गई थी लेकिन किसी ने परंपरा को तोड़कर एक महिला को दीक्षा देने की हिम्मत नहीं जुटाई। लेकिन संत रविदास ने केवल मीराबाई को ही दीक्षा नहीं दी, बल्कि अनेकों महिलाओं को शिक्षा देकर ये सिद्ध किया कि आध्यात्म के मार्ग पर चलने का अधिकार महिलाओं का भी उतना ही है जितना कि पुरुषों का। संत रविदास की समतावादी शिक्षाओं और महिलाओं को दिए गए दीक्षा के अधिकार से यथास्थितिवादी लोग भयभीत थे कि कहीं धर्म के नाम पर चलने वाली उनकी दुकानदारी बंद न हो जाए इसलिए संत रविदास के कुछ लोग घोर विरोधी हो गए। एक मत के अनुसार, संत रविदास जब राजस्थान के चितौड़गढ़ में अपनी शिष्या रानी झाली के आमंत्रण पर चितौड़गढ़ महल में भोजन करने के लिए भंडारे में गए तो उनके विरोधियों ने उनकी हत्या कर दी और एक झूठी कहानी फैला दी कि संत रविदास ने अपना सीना चीरकर सोने का जनेउ दिखाया और उसके बाद वो अन्तर्ध्यान हो गए। बहरहाल, उनकी मृत्यु की असली सच्चाई क्या है यह एक गहन शोध का विषय है जिस पर शोधकर्ताओं को शोध करने की आवश्यकता है।

गुरू रविदास और बौद्ध धम्म

गुरु रविदास और बौद्ध धम्म के सिद्धांतों-समानता, भ्रातृत्व, प्रेम व स्नेह में बहुत समानता है। इसलिए गुरु रविदास को श्रमण परंपरा का अग्रवाहक भी कहा जा सकता है। यद्यपि कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि संत रविदास का तथागत बुद्ध की शिक्षाओं से कुछ खास लेना-देना नहीं है। इसके लिए वे यह तर्क देते हैं कि तथागत बुद्ध ने तो गृहत्याग कर दिया था जबकि संत रविदास गृहस्थ थे। ऐसा तर्क देने वाले यह भूल जाते हैं कि तथागत बुद्ध और संत रविदास के बीच लगभग 2000 वर्षों का अंतराल था और इस बीच बौद्ध धर्म भी अनेक परंपराओं से गुजरा है। हमारे पड़ोसी देश वर्मा और जापान में अनेकों बौद्ध आचार्य गृहस्थ जीवन बिताते हैं। विपस्यना आचार्य श्री सत्य नारायण गोयनका गृहस्थ थे। इसी तरह गोयनका जी के गुरु सयाजी उबा खिन न केवल एक गृहस्थ थे बल्कि बर्मा के सरकार में महालेखाकार परीक्षक जैसे पदों पर तैनात रहते हुए बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार-प्रसार किया और उनको अपने जीवन में उतारा। तो क्या सयाजी उबा खिन को केवल इसलिए बौद्ध न माना जाए क्योंकि वो गृहस्थ थे और नौकरी करके अपनी रोजी-रोटी स्वयं कमाते थे ? इसलिए इस बारे में मेरा अपना मत है कि संत रविदास और तथागत बुद्ध की शिक्षाओं में न केवल समानता है बल्कि दोनों एक ही डोरी से बंधे नजर आते हैं और दोनों ही एक परंपरा के अलग-अलग समय के नायक हैं। गुरु रविदास ने तथागत बुद्ध की तरह ही मन की श्रेष्ठता को स्वीकारा है, बुद्ध ने कहा कि मन ही सर्वश्रेष्ठ है, गुरु रविदास ने भी कहा है-

मन ही पूजा मन ही धूप,
मन ही सेवा सहज सरूप।
पूजा अर्चना ना जानू तोरी,
कह रविदास कौन गति मोरी।
रविदास बाह्मन मत पूजिये,
जो होवे गुनहीन,
पूजही चरन चंडाल के,
जो होवे गुन ज्ञान प्रवीन ।

'यदि कोई ब्राह्मण गुणहीन है तो उसकी पूजा मत करो। यदि कोई चांडाल गुणवान है तो उसकी पूजा करो।'

बुद्ध ने भी वासल सुत्त में यह कह कर इस तरह की शिक्षा दी है। जन्म से ही किसी की जाति छोटी नहीं होती, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। मानव अपने कर्मो से नीच या ऊंच बनता है, अपने कर्मो से ही ब्राह्मण बनता है।

श्रावस्ती में अनाथपिंडक के जेतवन विहार में एक कुएं का नाम उनकी पत्नी लोना माई के नाम पर है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस कुएं के जल में त्वचा रोगों और खासकर कुष्ठ रोग को ठीक करने का गुण है। उत्तर भारत में लोग कई मंत्रों में लोना माई का नाम लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन मंत्रों में रोगों को ठीक करने की शक्ति होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि संत रविदास और उनकी पत्नी लोना देवी को आध्यात्मिक शक्तियां और रिद्धियां-सिद्धियां प्राप्त रही होंगी जिससे स्थानीय लोग प्रभावित हुए होंगे और इसलिए कुआं का नाम लोना माई के नाम पर रखा गया होगा और मंत्रों में उनका नाम लिया जाता रहा होगा। जेतवन में उनके नाम पर कुआं का मौजूद होना यह सिद्ध करता है कि वे श्रावस्ती जैसे बौद्ध स्थलों पर अनेक बार गए होंगे। इससे ये भी पता चलता है कि संत रविदास और उनकी पत्नी लोना देवी पर बुद्ध की शिक्षाओं का गहरा प्रभाव था। यहां पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्रावस्ती जो वाराणसी से इतनी दूर है वहां पर और वो भी जेतवन में जहां तथागत बुद्ध ने 25 वर्ष निवास किया हो और जो बौद्ध तीर्थस्थलों में अपना अहम स्थान रखता हो, वहां पर रविदास की पत्नी लोना माई के नाम पर कुआं कैसे बन गया ?

संत रविदास की लोकप्रियता का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि उनकी जन्म-जयंती माघ पूर्णिमा के दिन देश-विदेश से लाखों लोग उनकी जन्मस्थली मडुआडीह पहुंचते हैं और संत रविदास के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। पंजाब से संत रविदास के अनुयायी कई-कई स्पेशल रेलगाड़ियां बुक करवाकर ले जाते हैं। और अनेकों बसों से हजारों लोग बनारस जाते हैं।

संत रविदास के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारकर शील और सदाचार का जीवन जीएं, एक-दूसरे के प्रति प्रेम और सौहार्द की भावना रखें और जातिगत भेदभाव और असमानता छोड़ कर अपने देश भारत को सशक्त और मजबूत बनाने में अपना योगदान दें।

(लेखक बौद्ध धम्म के अध्येता व समतावादी विचारक हैं)

(साभार : सामाजिक न्याय संदेश)

DALITS NEED TO JOIN THE MAINSTREAM

Dr. Udit Raj

Elections to the first Lok Sabha were held in 1952. At that time, there was virtually no Dalit politics. There was not much of awareness about the importance of votes among Dalits and Adivasis. Even though Dr. Ambedkar was alive at that time, yet there was lack of awareness in them. Dr. Ambedkar had himself lost the election. With the passage of time, awareness among Dalits started increasing which gave rise to Dalit politics. In Maharashtra, Repulican Party of India came into existence but that had also a limited success. In the year 1960 decade, Dalit-Muslim Alliance politics got partial success in Western Uttar Pradesh. In 1993, Samajwadi Party-Bahujan Samaj Party alliance, resulted in powerful dalit politics. In the meanwhile, Bahujan Samaj Party made a new experiment by roping in non-Dalit votes presuming that Dalits in any case would vote for them, it would become easy for them to score victory for maximum seats. In Uttar Pradesh, Dalit-upper caste alliance was successful in 2007 but this miserably failed in the recent Lok Sabha elections. Today the big question is whether Dalits can be brought into the mainstream mainly through their own votes? Without Dalits coming into the mainstream, can they expect pro-Dalit policies?

The way political polarization has taken place under the leadership of Shri Narendra Modi during the 16th Lok Sabha elections, not only Dalit politics has been affected but regional parties have also been influenced. It had become crystal clear that without joining a mainstream party, effective policies for Dalits, Adivasis and the downtrodden cannot be made. It is just not sufficient that we make our presence felt but we should have a share in governance. It is only through a share in governance that we can bring about all round development and prosperity which in turn will strengthen the unity of the country. In the beginning, my colleagues were surprised at my suggestion but in the end I was able to convince and joined BJP on 24th February, 2014. This exercise was going on from October 2013 and it is a matter of great satisfaction that during the elections across the country, efforts of my supporters were commendable. This time, Dalits have given massive support to BJP. Their support to BJP should not be viewed lightly but it is based on their hope and confidence. Narendra Bhai Modi rightly said on 20.5.2014 in Parliament that people have voted BJP in to power for hope and confidence. No longer Dalits are comfortable with hallow slogans of dignity and pride and now demand is for delivery. getting fed up only with. They are eagerly looking forward for a share in governance and self-dependence. Mayawati became a symbol of Dalit politics but she also could not give delivery for which they had specifically joined her. Dalit employees and intellectuals were greatly disappointed that whatever facilities they were getting in the form of reservation, were also slipping out of their hands. Due to New Economic order , new avenues of employment and participation are being created but Dalits and Adivasis have not benefited from this policy. Both BJP and the Congress Party felt that Dalits and Adivasis were drifted towards dalit and regional parties because of this their interest towards Dalits and Adivasis diminished. This time during the elections, BJP got a big chunk of Dalit votes and they are hoping to get benefits from the government. On 2nd March, 2014, at his rally in Lucknow, Narendra Bhai Modi said that the coming decade will belong Backwards, dalits and the downtrodden which was very well received all over the country.

Bahujan Samaj Party got 19.6% votes in Uttar Pradesh in the Lok Sabha elections where the population of Dalits is 22%. Mayawati said on 17.5.2014 that her vote bank has not come down which is not correct. She gives tickets only to those persons who are in position to muster their personal or caste votes around 2 lacs. In that case, what happened to these votes? She claimed that dalit vote bank is intact and then where have candidates, votes gone? The fact is that this time a big chunk of Dalit votes has gone to BJP. Mayawati is trying to keep her vote-bank intact by psychologically misleading Dalits. The way Narendra Bhai Modi assured Dalits and the poor for their development on 20.5.2014 in the Central Hall of the Parliament, makes it clear that his Government will ensure them a share in governance in which case it seems quite possible that Dalits will come to the mainstream Bhartiya Janata Party in large numbers. Now Bhartiya Janata Party is no more a party of the upper caste people only. The way BJP has welcomed me and extended support has also created a great impact on Dalits all over the country that if they join hands with BJP, the party will extend them full respect and honour. The second best thing is that earlier the gap between Dalits and the upper caste which was widening is now abridging and I am quite confident that things will further improve. It is quite obvious that a party whose ultimate goal is a strong and powerful India will ensure that all sections of the society get respect and a share in governance. Nationalism, art and culture are safe only people have got control over the political power. It is a golden opportunity for BJP that by giving a share not only in governance to Dalits, it should strengthen its political and social base.

BSP'S DALIT SUPPORT BASE IS ON THE DECLINE

New Delhi, 17th May, 2014. Dr. Udit Raj, MP and Special Invitee, National Executive, Bhartiya Janata Party, said that Ms Mayawati's nervousness was conspicuous at her press conference. She repeatedly said that BSP's Dalit vote bank is completely intact which is totally wrong. Just to hide the fact of a slide in her Dalit vote bank, she tried to twist the election results by quoting certain figures but there also she failed to prove her point. Dalit population in Uttar Pradesh is 23% and she has polled less than 20% votes. She said that this time, Muslims, Backwards and the upper caste people have not voted for her which against is completely wrong. The fact is that this time BJP has got more Dalit votes which fact has been acknowledged in many poll surveys. Survey of the election results is going on and shortly the facts will come on the surface. This time BSP fielded 21 strong Brahmin candidates who had their own support-base. At other places also, tickets were given to candidates on the basis of caste equations where they had their strong personal and caste-based support. Had the tickets not been given on these lines or BSP had not got the votes of their non-Dalit candidates, BSP would have got just 10% votes.

Dr. Udit Raj thanked all Dalits and downtrodden people in the country that they not been swayed by the caste factor and have voted for BJP for development and share in governance for all sections of the society and for making Modi Bhai Prime Minister.

Rest Page of 8...

DR. UDIT RAJ DECLARED ELECTED WITH A HUGE MARGIN

bearers of Safai Kamgar Confederation started coming from all over the country and made the people of the constitutency aware of the efforts made for the welfare of Dalits in the past and appealed to the people of the area to vote for Dr. Udit Raj.

In the election, Rakhi Birla of Aam Admi Party and Krishna Tirath of the Congress Party were the main rivals of Dr. Udit Raj. Dr. Udit Raj defeated his nearest rival Rakhi Birla by 1.06 lakh votes and registered a historic victory from North-West Delhi Parliamentary Constituency.

BJP's Udit Raj became victorious by getting 629860 votes. Rakhi Birla got 522842 votes. The victory margin was 1.06 lacs while the difference of votes between BJP and Congress candidates was 470287. Congress candidate and the sitting MP got 157242 votes.

On the 16th May, 2014, candidates and their supporters started coming to the counting stations right from the early morning. With the rise and fall in the trends in the counting of votes, there was change in the moods of the leaders and their supporters. At one point of time, during the counting, AAP candidate Rakhi Birla left the counting station taking it that she had lost the game. After she came to know that the margin was bridging, she returned to the counting booth again.

Dr. Udit Raj was leading from the beginning of the first to the 21st round. AAP candidate was continuously trailing behind Dr. Udit Raj. The Congress candidate trailed behind Dr. Udit Raj and Rakhi Birla after a few rounds. The situation became clear after the 7th round and the Congress candidate left the counting booth. In the eighth and 9th rounds, there was a margin of about 90,000 votes between the BJP and AAP candidates and finally Dr. Udit Raj was declared elected after defeating his closest rival Rakhi Birla by a huge margin.

It may not be out of place to mention here that Dr. Udit Raj is a national leader in Dalit politics. On this historic victory, Dr. Udit Raj gave credit to Narendra Modi Ji, all leaders and workers of BJP, local people and the entire Dalit community and extended his greetings to all of them.

On the occasion of victory, he heartily congratulated all the leaders and workers of BJP, local people, workers and office bearers of the All India Confederation of SC/ST Organization and workers and office bearers of Safai Kamgar Confederation .

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 17 ● Issue 13 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● 16 to 31 May, 2014

Expand The Confederation

Dr. Udit Raj

The All India Confederation of SC/ST Organisations came into existence mainly to oppose the five anti-reservation orders. It may be mentioned here that in the year 1997, Department of Personnel & Training had issued five anti-reservation orders and the Confederation was created for the withdrawal of these orders. That objective was achieved and afterwards the Confederation had to face many challenges from time to time which were faced squarely by launching dharnas and rallies. A social movement very rarely lasts upto 17 years and if it does, it is only an exception. Now the time has come that the Confederation should be expanded. So far the leadership of the Confederation has been in the hands of employees and officers. Lakhs of employees and officers associated with the Confederation have retired. It was also planned to take the activities of the Confederation to every nook and corner of the country which goal is yet to be achieved.

The political parties have nearly stopped talking about Dalit issues.The main reason for this situation is that they think that Bahujan Samaj Party corners their votes. At the same time this party itself, however, does not raise Dalit-Adivasi issues. Under these circumstances, there is a need for a powerful social movement. The Confederation could play this role by expanding its activities to every nook and corner of the country. The Congress Government has not done anything worthwhile during its 10-year rule. It is also a fact that our social movement has not been able to create a proper impact. All sorts of social activities were taking place under the aegis of the Confederation but they were lacking proper direction. These activities were confined to critical and ideological discussions. The Dalit community cannot get share in governance just by criticizing Brahminism. We shall have to struggle for our rights. I have now been elected to the Parliament. This will definitely give encouragement to the members and office bearers of the Confederation and we can take the activities of the Confederation to every part of the country. If we remain steadfast in our movement, the party will definitely give due weightage to our demands. We shall have to resolve to make the Confederation strong at village, tehsil and district level.

DR. UDIT RAJ DECLARED ELECTED WITH A HUGE MARGIN

Vinod Kumar

Dr. Udit Raj, National Chairman, All India Confederation of SC/ST Organizations, and a national figure in Dalit politics, contested election from North West Delhi Parliamentary Constituency in the recent Lok Sabha elections on BJP ticket for Dalit share in governance, development of the area and unity of the country. The day Dr. Udit Raj filed his nomination papers for election to the 16th Lok Sabha, the entire Dalit community and the people of North West Delhi were overjoyed and made up their mind to get him elected with a huge margin for the sake of development and social harmony.

All the activities relating to the election were organized from C-9/90, Sector 8, Rohini, New Delhi under the leadership of Shri Jai Bhagwan Aggarwal. Election offices were also set up in all the 10 Assembly constitutiences and BJP office bearers at the district and zonal office took active part in the election campaign with a view to get Dr. Udit Raj elected from the North West Delhi Parliamentary Constitutency.

Right from the day of filing of nomination paper of Dr. Udit Raj, leaders and office

Rest Page on 7...

From left : Dr. Preety Agarwal, Mrs. Seema Raj, Abhiraj, Dr. Udit Raj and others on the occasion of Victory.

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com Computer typesetting by N. K. Karn